खण्ड-2 संख्या-15

एकादश बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग-1 कार्यवाही प्रश्नोत्तर.)

सत्यमेव जयते

दिनांक : 19 जून, 1995 ई०

14.9.94 को एक परिवाद पत्र निगरानी विभाग में प्राप्त हुआ है।

2. क्या उसकी जांच अभी तक नहीं किया जा रहा है।

3. यदि हां तो सरकार अविलम्ब जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई करने का विचार रखती है नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री : 1. उत्तर स्वीकारात्मक है।

2. उत्तर नकारात्मक है। इसकी जांच महानिदेशक (निगरानी अन्वेषण) ब्यूरो, पटना द्वारा कराई जा रही है।

3. जांच की जा रही है। जाचोंपरान्त कार्रवाई की जायगी।

आउट पोस्ट की स्वीकृति

1174. श्री विजय कुमार गुप्ता – क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

1. क्या यह बात सही है कि सुपौल जिला के मरौना प्रखंड का बडहरा गांव एवं किसनपुर प्रखंड का खानपुर गांव 10–10 पंचायतों का मुख्य केन्द्र है जहाँ अपराध की घटनाओं की वृद्धि के मद्देनजर पहले भी आउट पोस्ट की स्थापना की गई थी जिसे बाद में खत्म कर दिया गया ।

2. यदि खंड (1) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर पुलिस आउट पोस्ट की स्वीकृति देने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक नहीं, तो क्यों ?

श्री लालू प्रसाद : 1. मरौनी प्रखंड के बड़हरा गांव तथा किसनपुर पंखड का खानपुर नौआबाखंर गांव, कोशी नदी के गर्भ में बसा है पूर्व में खानपुर में सशस्त्र बल की एक टुकड़ी कुछ दिनों के लिए रखा गया था, किन्तु करीब 3 वर्षों से वहाँ सशस्त्र बल नहीं रखा जा रहा है । वहां कभी भी ऑट-पोस्ट नहीं था और न अभी उसकी आवश्यकता है, चूँकि यह गांव कोशी नदी के बल्ट में है। इसलिए इस पूरे क्षेत्र में आवागमन की असुविधा है । पिछले एक वर्ष से बांध क्षेत्र के अन्दर डकैती या लूट का एक भी अपराध प्रतिवेदित नहीं हुआ है । वर्तमान में बड़हरा एवं खानपुर गांव की अपराध की स्थिति नियंत्रण में है।

2. उपरोक्त खंड में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी ।

बकाये का भुगतान

1176. श्री बीरबल शर्मा - क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

1. क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में चर्मोद्योग विकास निमग 1974 से स्थापित है और उसमें 700 से ज्यादा श्रमिक और कर्मचारी कार्यरत हैं।
2. क्या यह बात सही है कि उपयुक्त निगम में कार्यरत कर्मचारियों एवं श्रमिकों बकाया भुगतान करने में 4.00 करोड़ रुपये राशि की आवश्यकता है।
3. यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उर्पयुक्त कर्मचारियों के कब तक बकाये का भुगतान करने का विचार रखती है ?

प्रभारी मंत्री : 1. उत्तर स्वीकारात्मक है।